>

Title: Need to accord approval for electrification of hamlets (majras) under Rajiv Gandhi Grameen Vidyutikaran Yojana in Uttar Pradesh and ensure supply of electricity to villages covered under the scheme particularly in Deoria parliamentary constituency.

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार ने लागू की । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सभी मजरों के विद्युतीकरण के लिए धनराशि की मांग की थी । उस समय केन्द्र सरकार ने कहा कि सभी प्रदेशों में सभी गाँवों का विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो जाये तो मजरों के विद्युतीकरण किये जाने की स्वीकृति दी जायेगी । खेद की बात है कि कई प्रदेशों में मजरो की विद्युतीकरण कार्य को मंजूरी दे रही है परंतु उत्तर प्रदेश को अभी तक मंजूरी नहीं दी गयी है । जबकि उत्तर प्रदेश में देश के सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं । वर्ष 2009 को 1,37,060 मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने दिया परंतु केन्द्र सरकार ने संसदीय क्षेत्र रायबरेली एवं सुल्तानपुर अलावा किसी और जनपद की स्वीकृति नहीं दी है । इन सबके कारण अनुसूचित जाति के कई हजार गाँवों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है और ट्रंसफर्मर बन गये परंतु उन पर से कनेक्शन नहीं दिये गये हैं । मेरे संसदीय क्षेत्र देवरिया (उत्तर प्रदेश) के लार इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है एवं जहां पर दलित बस्तियां हैं जिसकी वजह से यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और बच्चों का पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है । कई जगहों पर खम्भे लग गये हैं, परंतु उन पर तार नहीं बिछाये गये हैं ।

सरकार से अनुरोध है कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समुचित ढंग से एवं समय पर इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयास किये जाये ।